

सीएम की खुली छूट, तारगेट पर नक्सली-आत्मसमर्पण करें या मध्यप्रदेश को छोड़ दें

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने फिलहाल टारगेट पर नक्सली है। सीएम की खुली छूट के बाद एजेंसियों की सक्रियता बालाघाट, मंडला समेत प्रभावित जिलों में बढ़ी हुई है। प्रत्येक नक्सली गतिविधियों पर नजर है। हर 15 दिनों में सीएम और सीएस समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र ने दो टूक कहा है कि जितनी जल्दी नक्सली समस्या खत्म करें, उतना अच्छा होगा। इस केंद्रीय छूट के बाद मप्र सरकार ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कई मुश्किलें खत्म कर दी हैं। सीएम ने गुरुवार को लिखालवाद के खिलाफ मोर्चे पर तैनात सभी विंग के प्रमुखों को बुलाकर समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने नया प्लान साझा किया है, जिसमें नक्सलियों को पूरी तरह ध्वनि करने को लेकर काम किया जाना है। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जेन कसायिया, डीजीपी कैलाश मकवाना सहित बड़े अफसर भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सुख्तमंत्री ने सभी विंग के प्रमुखों को कहा है कि संसाधनों की कमी नहीं है। बीते 5 वर्षों में 25 से अधिक नक्सली मारे। इन पर 4 करोड़ रुपये का इनाम शेषित था। सरकार ने नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी आत्म समर्पण प्रोत्साहन योजना पर नए सिरे काम शुरू किया है तो आम लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चौकियों को थाने में बदल दिया है।

महिला दिवस पर पेंशनर की अविवाहित-विधवा पुत्री को पेंशन देने की मांग

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

पेंशनर वेलफेर एसोसिएशन ने पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर पेंशनर की मृत्यु के बाद उसकी अविवाहित-विधवा तलाकशुदा/परित्यका पुत्री को केंद्र के समन आजीवन पारिवारिक पेंशन देने की मांग की है। प्रदर्शन अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि अपाकी अध्यक्षता में ही 13 मार्च 2020 को मात्रालय में पेंशनर फोरम की बैठक में विषयान्वित सम्पत्ति प्रस्ताव किया गया को प्रस्तुत किया गया था इसके बाद सिवंत समिति द्वारा भी इस विषय में अनुरोध किया गया है कि विपत्तिप्रस्त, पीड़ित, असहाय, निराश्रित अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यका पुत्री को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2025 को आजीवन पारिवारिक पेंशन देने के आदेश जारी किये जाएं।



विधानसभा सत्र में चर्चा का बजट कम, फिर उठे सवाल

दस मार्च से सत्र, सिर्फ 9 बैठकें

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

मप्र विधानसभा का दस मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र की अवधि को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। यह सत्र सिर्फ 15 दिनों का है और नौ ही बैठकें होंगी। दरअसल पिछले 25 साल में विस सत्र और खासकर बजट सत्र की अवधि लगातार छोटी हो रही है। 2001 में जहां बजट सत्र 76 दिनों का था, वहां अब ये घटकर 15 दिन रह गया है। विपक्षी कांग्रेस ने इस पर विरोध दर्ज कराया है। दस मार्च को राज्यपाल के अधिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। वाहाना के 12 मार्च को वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे। सत्र के बीच होली की अवधि थी रहेगी।

खास बात यह है कि यह वर्ष बीज बजट सत्र सिर्फ 5 दिन चला था। सत्र बीच में खत्म होने पर कई बार जनहित के मुद्दों पर चर्चा भी अधूरी रहने की बात आती ही है। बजट चर्चा में प्रदेश की वित्तीय हालत से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले चर्चा में आते हैं। हालांकि

2001 में बजट सत्र 76 दिन का था जिसमें 27 बैठकें हुई थीं। वहीं, 2002 और 2003 में बजट सत्र में 28-28 बैठकों में सरकार का कामकाज हुआ। हालांकि इसके बाद सत्र की अवधि कम होती गई है। नेता प्रतिष्ठक उमंग सिंघार ने कहा कि पहले एक से डेढ़ माह बजट सत्र चलता था पर इस बार सिर्फ 9 दिन का रखा है। भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है।

एक दिन चला था सत्र !

साल 2020 में बजट सत्र सिर्फ एक दिन ही चला था। तलाकीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। बाद में भाजपा सरकार सत्र में आई और कोरोना काल के बीच सिंतंबर में 3 दिन का बजट सत्र रखा गया। ये सत्र एक दिन में ही बजट पेश होने के बाद स्थगित हो गया। वहीं 2015 में बजट सत्र में सिर्फ 7 बैठकें, 2022 में 8 बैठकें हो पाई थीं। मिछूने साल जुलाई में योग्य यादव सरकार ने पहला बजट पेश किया था। हालांकि हालामे के बीच सत्र 5 बैठकों के बाद ही स्थगित हो गया था।

एमपीपीएसरी: साक्षात्कार के लिए 26 तक जमा करें जरूरी दस्तावेज

एनसीटीई-बीसीआई कोर्स शुरू करने की तैयारी

भोपाल. दोपहर मेट्रो। राज्य सेवा मुख्य परिषाक 2024 से चयनित हुए अध्यर्थियों के साक्षात्कार की सूची मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएसरी) ने जारी की है। इस सूची में 339 अध्यर्थियों के नाम शामिल हैं। उक्त अध्यर्थियों को अगस्त में होने वाले साक्षात्कार में शामिल होने 26 मार्च तक अपने दस्तावेज एमपीपीएसरी 27 मार्च से तीन अप्रैल तक तीन हजार रुपय के विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज जमा करेगा। यहां भी अध्यर्थी दस्तावेज देने से चूक जाते हैं, तो उन्हें 25 हजार रुपय के विलंब शुल्क के साथ चार से 11 अप्रैल तक दस्तावेज जमा करने की दशा में अध्यर्थियों को 27 मार्च से 3 अप्रैल तक तीन हजार का विलंब शुल्क देगा होगा। यहां भी दस्तावेज देने से रह जाते हैं, तो उन्हें चार से 11 अप्रैल तक दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जाएगा।

एमपीपीएसरी की अध्यर्थियों को अगस्त में होने वाले साक्षात्कार में शामिल होने 26 मार्च तक अपने दस्तावेज एमपीपीएसरी 27 मार्च से तीन अप्रैल तक तीन हजार रुपय के विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज जमा करेगा। यहां भी अध्यर्थी दस्तावेज देने से चूक जाते हैं, तो उन्हें 25 हजार रुपय के विलंब शुल्क के साथ चार से 11 अप्रैल तक दस्तावेज जमा करने की दशा में अध्यर्थियों को 27 मार्च से 3 अप्रैल तक तीन हजार का विलंब शुल्क देगा होगा। यहां भी दस्तावेज देने से रह जाते हैं, तो उन्हें चार से 11 अप्रैल तक दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जाएगा।

पहली बार मजबूती से मांगी केंद्र सरकार से राज्य की हिस्सेदारी

16वें वित्त आयोग के सामने मप्र सरकार ने रखी अलग-अलग क्षेत्रों में मांगे

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

केंद्र के सामने लंबे समय बाद राज्य सरकार ने मजबूती से अपने हिस्से की हिस्सेदारी मांगने की तरह रही। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कायदादालिखा—पही में 300 से अधिक पर्सों का मेमोरेंड आयोग के अध्यक्ष डॉ।

अर्थविदं पनार्टिया को सौंपा। जिसमें कहा है कि अपी



कहा—राज्य में अपारवन संपदा, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, यहां देश के 10 फीसद आदिवासी इसलिए जरूरी कर्ताओं में बढ़ाई जाए हिस्सेदारी

अधिक राशि खर्च होती है, इसलिए अतिरिक्त वित्तीय मदद मिले। वन क्षेत्रों में मौजूदा मापदंडों के साथ-साथ खुले वन क्षेत्रों के संवर्धन का भी प्रावधान हो।

आपादा राहत में खर्च की अनुमति दें राज्य जलवाया और आपादा जोखिम प्रबंधन निधि में अंशदान 75 फीसद से बढ़ाकर 90 फीसद करें। कुल अंशदान में से 15 फीसद राज्य जलवाया परिवर्तन निधि, 70 फीसद राज्य आपादा शमन निधि के तहत खर्च करने की अनुमति के साथ खर्च में लचीलेपन की व्यवस्था करें। ये भी कहा कि राज्य विशिष्ट आपादाओं के लिए निधियों के 10 प्रतिशत उपयोग की सीमा को हटाया जाए। एकल जोखिम के लिए एसडीएमएफ निधि के तहत अधिकतम 50 फीसद उपयोग के प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए।

हस्तांतरण कर 70 फीसद तक बढ़ाया जाए

योग्य कोई उप कर या अधिकार लागता तो अधिकार की व्यवस्था से पूछा जाए। यदि इस अनुशंसा को माया किया जाता है तो उपकर और अधिकार की अधिकार को सकल कर राजस्व (जीटीआर) के 10 प्रतिशत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए) तक समिति किया जाना चाहिए। केंद्र व राज्यों के बीच होने वाले कुल हस्तांतरण में वर्तमान जलवाया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग में यह 53 व 14वें वित्त आयोग में 62 प्रतिशत था।

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का मत

- आयोग के अध्यक्ष डॉ. अर्थविदं पनार्टिया विकास होगा तो शहरीकरण भी होगा। यह जलसी है लेकिन इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। रोजगार निर्माण की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलना चाहिए। आयोग पर विकसित भारत के लिए रोडमैप बनाने की चुनौती है। वित्त आयोग सभी राज्यों के साथ संवाद कर रहा है। संवाद सत्रों के बाद आयोग के सभी विशेषज्ञ सदस्यों के साथ परामर्श कर राज्यों को वित्तीय संसाधनों के आवरण पर निर्णय लिया जा सकेगा।

- आयोग के सदस्य डॉ. मनोज पांडा, मध्यप्रदेश में विकास के कार्यक्रमों और नवाचारी पहल अच्छी है।

- आयोग के सदस्य एन.जा.ने कहा कि बीते वर्षों में मध्यप्रदेश सबसे ज्यादा आधिक व

नगरीय विकास अभियान के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न पीएम आवास योजना के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा करवाएं सभी सीईओःकलेक्टर

■ शहरी क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर व्यापक कार्यवाही करें नगर पालिकाएं

■ ग्रीष्मकाल में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए असर्थी माध्यमों से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए

नर्मदापुर, दोपहर मेट्रो

नर्मदापुरम् लक्ष्य निर्धारित कर पीएम आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। शहरी क्षेत्र की सीमाओं में अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही करें सभी नगर पालिकाएं। जिले की किसी भी निकाय में जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित करें सभी नगर पालिका अधिकारी। उक्त निर्देश कलेक्टर सेवन्या मीना ने गुरुवार को आयोजित नगरीय विकास अभियान के तहत चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

उद्देश्य निकायवाच सिर्फी कार्यों, विकास कार्यों, योजनाओं, आदि की समीक्षा की। कलेक्टर



सुश्री मीना ने पीएम आवास योजना

शहरी के तहत कुल प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप किया गए कार्य एवं अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 4 माहों में अपूर्ण कार्यों को निराकृत करने का लक्ष्य निर्धारित करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी नगर पालिका अधिकारी आवासों की जानकारी अनुसार चिन्हित करें कि कितने आवास अपूर्ण हैं उन्हें सर्वप्रथम पूरा किया जाए एवं साथ ही इसका प्रारंभ होने की स्थिति में नहीं है उन्हें सरेंडर करने की कार्यवाही करें।

कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि ठोस कार्यवाची बनाकर आगामी जून माह तक अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की संख्या को

शून्य किया जाए। अभियान मोड में इस कार्यों को सुनिश्चित करे सभी सीईओ।

इसी प्रकार जियोटेंगिंग मॉनिटरिंग तथा किस्तों को जारी किए जाने में विनियोगी भी प्रकार का विलंब न हो इसका ध्यान रखें। साथ ही कलेक्टर ने निकायवाच वसूली एवं मांग की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उद्देश्य दिए कि वसूली के मापदंशों में जल संकट के अनुरूप वसूली की जाए एवं नियमित रूप से इसका फलों अपूर्ण भी सुनिश्चित करें।

समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शहरी सीमाओं के भीतर अतिक्रमण पर अधिक प्रभावी कार्यवाही किए जाने की

ध्यान रखें, कलेक्टर ने मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड उक्त निर्देश देते हुए कहा की योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में गति बनाए रखें साथ ही कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा कि योजना अंतर्गत खराब गुणवत्ता रेसेवरेशन कर में विलंब को करते हुए स्टॉकर नहीं किया जाए। संबंधित संस्था जबवादीरा पूर्ण तरीके से कार्य संपन्न करें।

पेयजल व्यवस्था को निर्बंध एवं सुचारू रूप से जारी रखें

कलेक्टर ने आगामी ग्रीष्म काल को दृष्टित रखते हुए सभी सीमाओं को निर्देश दिए की समस्त नयीरी निकायों में पेयजल की निर्बंध अपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करा जाए। जिन निकायों में जल संकट जैसी समस्याओं की संभावना हो उन स्थानों को चिन्हित कर टैकर आदि से जलांशुमि की अस्थाई व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करों।

समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शहरी सीमाओं के भीतर अतिक्रमण पर अधिक प्रभावी कार्यवाही किए जाने की

आवश्यकता है। इसके लिए उद्देश्य निर्देश दिए कि निकायों में अतिक्रमण के विरुद्ध ध्यान को चिन्हित कर वहाँ से अतिक्रमण होते हुए कार्यवाही की जाए। साथ ही जनप्रतिनिधि द्वारा बैठक में उद्देश्य स्पष्ट किया कि सभी सुचिय नगर पालिका अधिकारियों को यह जबवादीरा है कि अपने-अपने थेट्रों में गम्भीर पूर्वान्वयन के बावजूद अतिक्रमण, शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा, दुकानों को व्यवस्थित करने से जारी रखें।

पेयजल व्यवस्था को निर्बंध एवं सुचारू रूप से जारी रखें

कलेक्टर ने आगामी ग्रीष्म काल को दृष्टित रखते हुए सभी सीमाओं को निर्देश दिए की विलंब न हो इसका ध्यान रखें। साथ ही कलेक्टर ने निकायवाच वसूली एवं मांग की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उद्देश्य दिए कि विलंब न होते हुए किया जाए। जिन निकायों में जल संकट जैसी समस्याओं की संभावना हो उन स्थानों को चिन्हित कर टैकर आदि से जलांशुमि की अस्थाई व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करों।

समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शहरी सीमाओं के भीतर अतिक्रमण पर अधिक प्रभावी कार्यवाही किए जाने की

ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण



नर्मदापुर, दोपहर मेट्रो

मनोज गुणवान, ए.डी.आई.ओ.

एन.आई.सी. श्रेणी उपास एवं जिला प्रबंधक ईंगवरेंस संसदीप चौरसिया द्वारा अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशनुसार जिला स्तर पर स्थित कार्यालयों में पदथ

अधिकारियों, कर्मचारियों को ई-कार्यालय प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी त्रैमासी बूझदारी के बावजूद अधिकारियों ने उद्देश्य के लिए भूमियों पर अवैध कब्जा, दुकानों को व्यवस्थित करने से जारी रखें।

प्रशिक्षण में डी.आई.ओ.

एन.आई.सी. मनोज गुणवान ने बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का सही और प्रभावी उपयोग सिखाया जा रहा है, ताकि कार्यों को डिजिटल रूप से सुचिवस्थित किया जाए।

डी.आई.ओ. एन.आई.सी.

मनोज गुणवान ने

बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

हालांकि डी.आई.ओ. एन.आई.सी.

मनोज गुणवान ने

बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का सही और प्रभावी उपयोग सिखाया जा रहा है, ताकि कार्यों को डिजिटल रूप से सुचिवस्थित किया जाए।

एन.आई.सी. मनोज गुणवान ने

बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

डी.आई.ओ. एन.आई.सी.

मनोज गुणवान ने

बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का सही और प्रभावी उपयोग सिखाया जा रहा है, ताकि कार्यों को डिजिटल रूप से सुचिवस्थित किया जाए।

डी.आई.ओ. एन.आई.सी.

मनोज गुणवान ने

बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

डी.आई.ओ. एन.आई.सी.

मनोज गुणवान ने

बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

डी.आई.ओ. एन.आई.सी.

मनोज गुणवान ने

बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

डी.आई.ओ. एन.आई.सी.

मनोज गुणवान ने

बताया कि विभागों में कार्यप्रणाली को डिजिटल और कृशल बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

डी.आई.ओ. एन.आई.सी.

डायवर्सन के गड़बड़ झाले में प्रशासन कर रहा करवाई की तैयारी

वेयरहाउस मलिक, मैरिज गार्डन, खूल व होटल संचालक लगा रहे शासन को घूना

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

डायवर्सन के नाम पर बड़े गड़बड़ झाले को अंजाम विकास खांड में दिया जा रहा जितनी जगह कागजों में दर्शाया है उससे अधिक शृंखला का उपयोग करके के इस खेल को अंजाम देने तथा सरकार को हर साल राजस्व ना देना पड़ा उपरे लिए नए-नए तिकड़म लाने का काम विकास खांड में बखूबी किया जा रहा है। यह सब इनके द्वारा केवल डायवर्सन की राशि कम चुकाने के लिए ज्यादातर बड़े कारोबारियों के द्वारा जितनी जगह का उपयोग व्यापार करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों के द्वारा केवल 25 से 30 प्रतिशत जगह का ही संकरी किंवदं में डायवर्सन करकर बाकी जगह का उपयोग के लिए वास्तव में नहीं किया जा रहा है शासन के रिकॉर्ड में नहीं होने से लालोंका नुकसान सरकार को प्रतिवर्ष हो



रहा है। ऐसा करने वालों में काम में अधिकांश वेयरहाउस मलिक, मैरिज गार्डन संचालक बड़े-बड़े स्कूल चलाने वाले, होटल और उद्योग संचालित करने वाले एवं कई व्यवसाईयों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, इनकी जांच करने के लिए कोई जाता नहीं है पटवारी आर आई कागजों में खानापूर्ति करते रहते हैं। इस काम को नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों में जिनें भी वेयर हाउस और बड़े कारोबार करने वाले ज्यादातर लोग के द्वारा पर एक तरफ से जांच के बाद सही कारवाई होती है। इन्होंने व्यवसाय करने के लिए शासन के नाम पर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है जितनी भी कॉलोनी यहां पर विकसित होती है। जो कि अवैध रूप से बन रही है उनके डायवर्सन की भी सही जांच हो जाए तो इस काम में भी गड़बड़ी साबित हो सकती है। कॉलोनीजर ने जितनी जगह का डायवर्सन करवाया है उसे दुगनी में जगह में कॉलोनी काटकर प्लाट बेचना है। कुछ कॉलोनी काटने वालों ने तो डायवर्सन कराए बगैर शासन प्रशासन के अधिकारी कुछ नहीं कर रहा है। इन्होंने जो

खानापूर्ति के लिए इस काम करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगाना क्योंकि इस काम को करने वालों को कई अधिकारी कर्मचारियों संस्थान प्राप्त होता है उनकी मिली भगत से ही तो इस काम को ही इतने सालों से करते आ रहा है।

कॉलोनी काटने वाले भी नहीं हैं पीछे

अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों के द्वारा भी डायवर्सन के नाम पर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है जितनी भी कॉलोनी यहां पर विकसित होती है। जो कि अवैध रूप से बन रही है उनके डायवर्सन की भी सही जांच हो जाए तो इस काम में भी गड़बड़ी साबित हो सकती है। कॉलोनीजर ने जितनी जगह का डायवर्सन करवाया है उसे दुगनी में जगह में कॉलोनी काटकर प्लाट बेचना है। कुछ कॉलोनी काटने वालों ने तो डायवर्सन कराए बगैर शासन प्रशासन के अधिकारी

इन सब की भी एक तरफ से जांच हो तो शासन को लालोंको रहा। राजस्व के रूप में इन लोगों से मिल सकते हैं। पर ऐसा करने की हिम्मत अधिकारी कर्मचारी जूट पाएंगे या तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा अधिकांश पटवारियों एवं आर आई की भूमिका भी डायवर्सन में महत्वपूर्ण रहती है। इनके द्वारा अपने काम को गंभीरता से नहीं किया जाता है वह जानवृकर अनेकों करके सरकार को तुकसान पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहा है।

इनका कहना है
डायवर्सन के नाम पर यदि किसी ने भी गलत किया है तो हम जांच के बाद करवाई करेंगे कलेक्टर ने भी डायवर्सन में वृद्धि करने के लिए दिशा दिए।
—हर्षल घौसी एसडीएम

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजनातंत्र ने 160 जोड़े विवाह बंधन में बंधे



विदिशा, दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना अंतर्गत आज विदिशा के श्रीरामतीला मेला प्रागंग में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रमेश विदिशा जनपद अध्यक्ष श्री वीर सिंह रघुवंशी सहित अन्य जनपत्रियों के अलावा जिला पंचायत के अतिरिक्त



विवाह हुआ है। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना अंतर्गत आज विदिशा के श्रीरामतीला मेला में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रमेश विदिशा जनपद अध्यक्ष श्री वीर सिंह रघुवंशी सहित अन्य जनपत्रियों के अलावा जिला पंचायत के अतिरिक्त

समृद्धि योजना अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों का प्रशिक्षण आयोजित



विदिशा, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश जन अधिकारी परिषद जिला विदिशा द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन जिला पंचायत के सभागार में गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री वर्षभूषण आचार्य, संभाग सम्बन्धक भौपाल, श्रीमति पूजा बंधेया जिला समन्वयक, विदिशा एवं श्री अमित कुमार दधीच संस्था भौपाल के एजीक्यूटिव डियरेक्टर द्वारा स्वैच्छिक संगठन की संरचना एवं प्रबंधन विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में उपस्थित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का प्रस्तुति किया गया।

म. प्र. जन अधिकारी परिषद जिला विदिशा की जिला समन्वयक श्रीमती पूजा बंधेया जिला समन्वयक

का परिचय कराते हुए जन अधिकारी परिषद की अवधारणा का प्रस्तुतीकरण किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सभा में श्री वर्षभूषण आचार्य, संभाग सम्बन्धक भौपाल द्वारा परिषद द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तृत विवरण आयोजन को लेकर होने ही आयोजित कार्यक्रम की विस्तृती के बारे में जिला पंचायत के सभागार में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका के विषय में अवगत कराया। श्री अमित कुमार दधीच एजीक्यूटिव डियरेक्टर द्वारा स्वैच्छिक संगठन की संरचना एवं प्रबंधन विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। श्री अमित कुमार दधीच एजीक्यूटिव डियरेक्टर द्वारा स्वैच्छिक संगठन की संरचना एवं प्रबंधन विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुए विदुतियों के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण में उपस्थित स्वैच्छिक

संगठनों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद्युतियों का प्रस्तुति किया गया।

प्रशिक्षण के अनुपात में विद

2000 में न्यूजीलैंड ने टाइटल जीता, टीम इंडिया को 63 फीसदी आईसीसी मैच हराए

25 साल बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भिड़ेगे भारत-न्यूजीलैंड

नईदिल्ली, एजेंसी

भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर एक बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़े वाले हैं। दोनों 9 मार्च को दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। इससे पहले 2000 में नेरोनी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओरेव में 4 विकेट से जीता था। आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने ही भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया है। टीम भारत को 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप का फाइनल भी हरा चुकी है।

न्यूजीलैंड के पास लिमिटेड ऑर्वर्स क्रिकेट का इकलौता आईसीसी टाइटल चैंपियंस ट्रॉफी ही है। साल 2000 में भारत ने केन्या, ऑस्ट्रेलिया और साथ अफ्रीका को हारकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं न्यूजीलैंड ने जिज्याब्द और पाकिस्तान को हाराया। नेरोनी के मैदान पर फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फालिंग चुनी। भारत से कमान सौरव गांगुली ने 117 और सचिन तेंदुलकर ने 69 रन बनाए। इन दोनों के अलावा कोई और बैटर कुछ खास नहीं कर सका और टीम 6 विकेट खोकर 264 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड ने 132 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। वहाँ क्रिस कैरेस ने क्रिस हैरिस के साथ पारी संभाल ली। दोनों



ने छठे विकेट के लिए 122 रन की पार्टनरशिप की और भारत को मैच से बाहर कर दिया। कैरेस ने शतक कलगाया और 2 गेंदें बाकी रहते टीम को जीत दिला दी। कैरेस की 9 लाई और आफ द मैच भी रहे। चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी बार ही भिड़ेगी।

पिछों: 27 साल के चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में दोनों टीमें तीसरी बार ही भिड़ेगी। इसी साल रूप से जेंडे में भी दोनों का सामना हुआ, तब भारत ने दुबई के ही मैदान पर न्यूजीलैंड को 44 रन से हाराया था। अब 9 मार्च को फिर एक बार दोनों का सामना दुबई के मैदान पर ही होगा। आईसीसी के सभी टूर्नामेंटों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 मैच हुए। 10 में न्यूजीलैंड और

महज 6 में टीम इंडिया को जीत मिली। हालांकि, आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट में दोनों ने बराबरी के मैच ही जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप में दोनों के बीच 12 मैच हुए, 6 में न्यूजीलैंड और 6 में ही भारत को जीत मिली। हालांकि, न्यूजीलैंड की 3 में से एक जीत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आई। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में दोनों टीमें तीसरी बार ही भिड़ेगी। इसी साल रूप से जेंडे में भी दोनों का सामना हुआ, तब भारत ने दुबई के ही मैदान पर न्यूजीलैंड को 44 रन से हाराया था। अब 9 मार्च को फिर एक बार दोनों का सामना दुबई के मैदान पर ही होगा। आईसीसी के सभी टूर्नामेंटों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 मैच हुए। ये हर 2000 के

चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2019 के वनडे वर्ल्ड कप से मीपाइनल और 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मिली थी। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप

सेमीफाइनल में भारत ने इस ट्रॉफी को तोड़ा

और न्यूजीलैंड को 70 से हरा दिया।

आवरणों वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर दबदबा बनाए रखा है। दोनों के बीच 95 मैच हुए, 63 में भारत और महज 30 में न्यूजीलैंड को जीत मिली। यारी भारत का साक्षर्सेस रेट 66.7% रहा। दोनों ने 1 टाई और 1 बेनतीजा मैच भी खेला।

पिछले 10 साल में भारत ने 85

फीसदी वनडे हराएः भारत ने पिछले 10

साल में न्यूजीलैंड पर और भी ज्यादा दबदबा बना लिया है। 2016 से दोनों के बीच 20 वनडे हुए, 17 में भारत और महज 3 में न्यूजीलैंड को जीत मिली।

हालांकि, न्यूजीलैंड की 3 में से एक जीत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आई। भारत से खिलाफ कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में ट्रॉफी को जीत दिया। दोनों ने एक जीत और एक बेनतीजा दिलाया। दोनों के बीच 4 नॉकआउट मैच हुए, 3 में न्यूजीलैंड और महज 1 में भारत को जीत मिली। 2023 से पहले तक तो न्यूजीलैंड ने भारत को तीनों नॉकआउट मैच हराया था। ये हर 2000 के

पिछले 10 साल में भारत ने 85

फीसदी वनडे हराएः भारत ने पिछले 10

साल में न्यूजीलैंड पर और भी ज्यादा दबदबा बना लिया है। 2016 से दोनों के बीच 20 वनडे हुए, 17 में भारत और महज 3 में न्यूजीलैंड को जीत मिली।

हालांकि, न्यूजीलैंड की 3 में से एक जीत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आई। भारत से खिलाफ कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में ट्रॉफी को जीत दिया। दोनों ने एक जीत और एक बेनतीजा दिलाया। दोनों के बीच 4 नॉकआउट मैच हुए, 3 में न्यूजीलैंड और महज 1 में भारत को जीत मिली। 2023 से पहले तक तो न्यूजीलैंड ने भारत को तीनों नॉकआउट मैच हराया था। ये हर 2000 के

पिछले 10 साल में भारत ने 85

फीसदी वनडे हराएः भारत ने पिछले 10

साल में न्यूजीलैंड पर और भी ज्यादा दबदबा बना लिया है। 2016 से दोनों के बीच 20 वनडे हुए, 17 में भारत और महज 3 में न्यूजीलैंड को जीत मिली।

हालांकि, न्यूजीलैंड की 3 में से एक जीत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आई। भारत से खिलाफ कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में ट्रॉफी को जीत दिया। दोनों ने एक जीत और एक बेनतीजा दिलाया। दोनों के बीच 4 नॉकआउट मैच हुए, 3 में न्यूजीलैंड और महज 1 में भारत को जीत मिली। 2023 से पहले तक तो न्यूजीलैंड ने भारत को तीनों नॉकआउट मैच हराया था। ये हर 2000 के

पिछले 10 साल में भारत ने 85

फीसदी वनडे हराएः भारत ने पिछले 10

साल में न्यूजीलैंड पर और भी ज्यादा दबदबा बना लिया है। 2016 से दोनों के बीच 20 वनडे हुए, 17 में भारत और महज 3 में न्यूजीलैंड को जीत मिली।

हालांकि, न्यूजीलैंड की 3 में से एक जीत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आई। भारत से खिलाफ कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में ट्रॉफी को जीत दिया। दोनों ने एक जीत और एक बेनतीजा दिलाया। दोनों के बीच 4 नॉकआउट मैच हुए, 3 में न्यूजीलैंड और महज 1 में भारत को जीत मिली। 2023 से पहले तक तो न्यूजीलैंड ने भारत को तीनों नॉकआउट मैच हराया था। ये हर 2000 के

पिछले 10 साल में भारत ने 85

फीसदी वनडे हराएः भारत ने पिछले 10

साल में न्यूजीलैंड पर और भी ज्यादा दबदबा बना लिया है। 2016 से दोनों के बीच 20 वनडे हुए, 17 में भारत और महज 3 में न्यूजीलैंड को जीत मिली।

हालांकि, न्यूजीलैंड की 3 में से एक जीत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आई। भारत से खिलाफ कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में ट्रॉफी को जीत दिया। दोनों ने एक जीत और एक बेनतीजा दिलाया। दोनों के बीच 4 नॉकआउट मैच हुए, 3 में न्यूजीलैंड और महज 1 में भारत को जीत मिली। 2023 से पहले तक तो न्यूजीलैंड ने भारत को तीनों नॉकआउट मैच हराया था। ये हर 2000 के

पिछले 10 साल में भारत ने 85

फीसदी वनडे हराएः भारत ने पिछले 10

साल में न्यूजीलैंड पर और भी ज्यादा दबदबा बना लिया है। 2016 से दोनों के बीच 20 वनडे हुए, 17 में भारत और महज 3 में न्यूजीलैंड को जीत मिली।

हालांकि, न्यूजीलैंड की 3 में से एक जीत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आई। भारत से खिलाफ कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में ट्रॉफी को जीत दिया। दोनों ने एक जीत और एक बेनतीजा दिलाया। दोनों के बीच 4 नॉकआउट मैच हुए, 3 में न्यूजीलैंड और महज 1 में भारत को जीत मिली। 2023 से पहले तक तो न्यूजीलैंड ने भारत को तीनों नॉकआउट मैच हराया था। ये हर 2000 के

पिछले 10 साल में भारत ने 85

फीसदी वनडे हराएः भारत ने पिछले 10

साल में न्यूजीलैंड पर और भी ज्यादा दबदबा बना लिया है। 2016 से दोनों के बीच 20 वनडे हुए, 17 में भारत और महज 3 में न्यूजीलैंड को जीत मिली।

हालांकि, न्यूजीलैंड की 3 में से एक जीत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में आई। भारत से खिलाफ कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में ट्रॉफी को जीत दिया। दोनों ने एक जीत और एक बेनतीजा दिलाया। दोनों के बीच

